

झारखंड राज्य और अन्य

बनाम

टाटा कमिंस लि. और अन्य।

24 मार्च 2006

[एस.एच. कपाड़िया और अशोक भान, न्यायमूर्तिगण]

औद्योगिक नीति - निवेश को आकर्षित करने और राज्य में औद्योगिक विकास को बनाए रखने के लिए बिक्री कर में छूट - इसके अनुदान के लिए पूर्व शर्त यह है कि दावेदार के पास उस भवन पर विशेष स्वामित्व हो जिसमें कारखाना स्थित था, या यदि वह पट्टे की भूमि पर था या भवन लिया गया था पट्टे पर, भूमि या भवन या दोनों को पंजीकृत पट्टे द्वारा न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि के लिए अर्जित किया जा रहा है - कारखाने के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी से उनके भागीदार द्वारा उप-पट्टे पर ली गई भूमि पर लाभ के दावे की अस्वीकृति - उच्च न्यायालय ने लाभ की अनुमति दी है यह पाया गया कि दावेदार उस इमारत का विशेष मालिक था जिसमें फैक्ट्री स्थित थी, और उसने न केवल इकाई में पर्याप्त मात्रा में निवेश किया था, बल्कि कर के रूप में भी भुगतान किया था - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: इमारत का वस्तु स्वामित्व या 15 साल के लिए पट्टा, यह सुनिश्चित करना था यह उद्योग लाभ का लाभ लेने के बाद भाग नहीं गया - निवेश की गई और करों के रूप में भुगतान की गई पर्याप्त मात्रा को ध्यान में रखते हुए, दावेदार को फ्लाइबाई नाइट ऑपरेटर नहीं कहा जा सकता है, और यह औद्योगिक विकास और विकास में योगदान देगा - विशेष रूप से अनुमत छूट का लाभ छूट अधिसूचना की सख्त व्याख्या के बावजूद भी यह तभी दिया जाना चाहिए जब दावेदार उस इमारत का विशेष मालिक हो जिसमें फैक्ट्री स्थित थी।

क्रानून की व्याख्या - किसी अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट - यह कर दायित्व से छूट है - ऐसी छूट अधिसूचना को सख्ती से पढ़ा जाना चाहिए - हालाँकि, जब एक निर्धारिती को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कर छूट का वादा किया जाता है औद्योगिक नीति के संदर्भ में, अधिसूचनाओं को लागू करने को औद्योगिक नीति के संदर्भ में पढ़ा जाना

चाहिए - ऐसे मामले में, छूट अधिसूचनाओं को औद्योगिक नीति द्वारा परिकल्पित वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए उदारतापूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, न कि सख्त अर्थों में जैसा कि मामले में है। कर कानून के तहत दायित्व से छूट।

शब्द और वाक्यांश - कर- प्रकृति की- व्याख्या।

अपीलकर्ता ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बनाए रखने के लिए बिक्री कर छूट की परिकल्पना करते हुए एक औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति को दो अधिसूचनाओं, एसओ संख्या 478 और 479, दोनों दिनांक 22-12-1995 द्वारा लागू करने की मांग की गई थी। इन अधिसूचनाओं के तहत औद्योगिक नीति का लाभ देने के लिए पूर्व शर्तों में से एक यह थी कि मालिक/साझेदार/होलडिंग कंपनी का उस भवन पर अपना विशेष स्वामित्व होना चाहिए जिसमें इकाई का कारखाना स्थित है। हालाँकि, यदि इकाई का कारखाना पट्टे की भूमि पर या पट्टे पर ली गई इमारत में स्थापित किया गया था, तो छूट तब स्वीकार्य होगी जब ऐसी भूमि या भवन या दोनों को न्यूनतम 15 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे के माध्यम से अधिग्रहित किया गया हो। पट्टा इकाई के मालिक या फर्म के किसी भागीदार या होलडिंग कंपनी के पक्ष में होना था।

प्रत्यर्थीने इन छूटों के लाभ का दावा किया। हालाँकि, यह पाया गया कि जिस भूमि पर उनके द्वारा कारखाने का निर्माण किया गया था, वह किसी अन्य कंपनी से उनके संयुक्त उद्यम भागीदार की उप-पट्टे पर दी गई भूमि थी, और बाद के दोनों के बीच समझौते के अनुसार, संयुक्त उद्यम भागीदार को इसका हिस्सा आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं था। वह जमीन किसी अन्य कंपनी को दे दी जाए। इसलिए छूट के लिए उनका दावा खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके पास उस भूमि पर न तो कानूनी स्वामित्व था और न ही स्वामित्व था जिस पर कारखाना स्थापित किया गया था; न ही वे 15 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत करने की स्थिति में थे।

प्रत्यर्थीने अपने दावे की अस्वीकृति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें पाया गया कि वह उस इमारत का विशेष मालिक था जिसमें कारखाना स्थित था। प्रत्यर्थीको उनका लाभ देने का अधिकार देने के साथ छूट अधिसूचना की शर्तों का अनुपालन किया जाना पाया गया। यह भी

पाया गया कि प्रत्यर्थीने परियोजना में 302 करोड़ रुपये का निवेश किया था और लगभग 600 करोड़ रुपये का कर चुकाया था। इसके विरुद्ध अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित किया : 1. कर सामान्य राजस्व जुटाने के लिए एक भुगतान है। यह एक बोझ है। यह भुगतान करने की योग्यता या क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है। यह राज्य की कर लगाने की शक्ति का प्रकटीकरण है। किसी अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट कर दायित्व से छूट है। इसलिए, ऐसी प्रत्येक छूट वाली अधिसूचना को सख्ती से पढ़ा जाना चाहिए। हालाँकि, जब एक निर्धारिती को औद्योगिक नीति की शर्तों के रूप में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कर छूट का वादा किया जाता है, तो कार्यान्वयन अधिसूचनाओं को औद्योगिक नीति के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। ऐसे मामले में, छूट अधिसूचनाओं को औद्योगिक नीति द्वारा परिकल्पित वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए उदारतापूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, न कि सख्त अर्थों में, जैसा कि कर कानून के तहत दायित्व से छूट के मामले में होता है।

2.1. भवन के स्वामित्व या 15 वर्षों के लिए पट्टे पर जोर देने का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि वे उद्योग नीति के तहत दिए गए लाभ का लाभ लेने के बाद भाग न जाएं और कंपनी वास्तव में एक वास्तविक निवेशक थी राज्य में उचित अवधि के लिए चलाए जाने वाले उद्योग में पूंजी। [449-बी]

2.2. इसी पृष्ठभूमि में किसी को प्रत्यर्थी द्वारा किए गए निवेश को देखना होगा। उन्होंने 302 करोड़ रुपये का निवेश किया था, 800 से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया था और लगभग रुपये का कर चुकाया था। 600 करोड़। इन तथ्यों के संदर्भ में, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रत्यर्थी फ्लाईबाई नाइट ऑपरेटर नहीं है। उपरोक्त आंकड़े विवादित नहीं हैं। प्रत्यर्थी द्वारा स्थापित उद्योग राज्य की औद्योगिक वृद्धि और विकास में योगदान देगा।

3. भले ही कोई अधिसूचना(अधिसूचनाओं) की सख्त व्याख्या पर जाए, उच्च न्यायालय की राय सही थी कि अधिसूचना(अधिसूचनाओं) का पहला भाग, दूसरे भाग से अलग, 'भूमि' का उल्लेख नहीं करता है '। यदि विभाग के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए कि अधिसूचना का पहला भाग केवल तभी लागू होगा जब प्रत्यर्थी उस भूमि और भवन का मालिक हो जिसमें उसका

कारखाना स्थित है, तो यह न केवल अधिसूचना की एक संकीर्ण व्याख्या कर रहा है जो अधिसूचना को विफल कर देगा। प्रोत्साहन नीति में अंतर्निहित उद्देश्य, लेकिन यह उक्त अधिसूचना (अधिसूचनाओं) के मूल पाठ के विरुद्ध भी होगा, जिसमें अधिसूचना के पहले भाग से 'भूमि' शब्द हटा दिया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 10272/2003।

रिट याचिका (टी) संख्या 2587, 2003 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 31/7/2003 से।

2004 की सिविल अपील संख्या 1006 और 2005 की टी सी (सी) संख्या 40 के साथ।

अपीलकर्ता की ओर से अजीत कुमार सिन्हा एवं गोपाल प्रसाद।

टी आर अंध्यारुजिना, पल्लव सिशोदिया, एस सुकुमारन, सुश्री। सुषमा शर्मा , अखिल छाबड़ा, प्रतिवादियों की ओर से कनिका गोम्बर और राजन नारायण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

कपाड़िया, न्यायाधीश सिविल अपील संख्या 10272 OF 2003 विशेष अनुमति की मंजूरी द्वारा यह सिविल अपील झारखंड उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 31/07/2003 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि टाटा कमिंस लिमिटेड, बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के तहत एक निर्धारिती, दिनांक 22/12/1995 की अधिसूचना संख्या 478 और 479 दोनों के साथ पठित औद्योगिक नीति, 1995 के लाभ का हकदार है। आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ता - बिहार वित्त अधिनियम के तहत राज्य और वाणिज्यिक कर विभाग को 1/4/2004 से शुरू होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए निर्धारिती से बिक्री कर बकाया के लिए 54.5 करोड़ रुपये की वापसी योग्य राशि को समायोजित करने का निर्देश दिया जाता है। .

इस सिविल अपील को पृष्ठभूमि देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

वर्ष 1993 में, बिहार सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से एक औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। वर्ष 1995 में इस नीति में आंशिक संशोधन किया गया। अपने परिचय में, नीति ने राज्य के संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक वातावरण बनाने, तेजी से औद्योगीकरण के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा प्रदान करने, आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न करने के लिए निवेश आकर्षित करने, संभावित रूप से व्यवहार्य और बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए नीति के लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित किया। , राज्य में निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना। प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में, नीति में नवीनीकरण के विकल्प के साथ 99 वर्षों के लिए पट्टे पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कॉर्पोरेट्स को ग्रोथ सेंटरों में भूमि के आवंटन की परिकल्पना की गई है। इसमें निवेश को आकर्षित करने और राज्य में औद्योगिक विकास को बनाए रखने के लिए बिक्री कर में छूट की भी परिकल्पना की गई है। तदनुसार, नई इकाइयों को पॉलिसी के खंड 16(1) में परिकल्पित अवधि के दौरान कच्चे माल की खरीद पर बिक्री कर की उनकी पसंद के अनुसार "सेट ऑफ " या "छूट" की सुविधा दी गई थी। इसी प्रकार, खंड 16(2), तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर पर छूट/सेटऑफ का लाभ नई इकाइयों को विकल्प के साथ दिया गया था कि वे या तो बिक्री कर के भुगतान को स्थगित कर दें या उसमें उल्लिखित अवधि के लिए बिक्री कर में छूट चुनें। बिक्री के संबंध में यह नीति कर प्रोत्साहन को दो अधिसूचनाओं, एसओ संख्या 478 और 479 दोनों दिनांक 22/12/1995 द्वारा लागू करने की मांग की गई थी। उपरोक्त अधिसूचनाओं के तहत औद्योगिक नीति, 1995 के लाभ के अनुदान के लिए पूर्व शर्तों में से एक यह थी कि मालिक /साझेदार/होलडिंग कंपनी का उस भवन पर अपना विशेष स्वामित्व होना चाहिए जिसमें इकाई का कारखाना स्थित है। हालाँकि यदि इकाई का कारखाना पट्टे की भूमि पर या पट्टे पर ली गई इमारत में स्थापित किया गया था, तो छूट तब स्वीकार्य होगी जब ऐसी भूमि या भवन या दोनों को न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे के माध्यम से अर्जित किया गया हो। पट्टा इकाई के मालिक या फर्म के किसी भागीदार या होलडिंग कंपनी के पक्ष में होना था।

टाटा कमिंस लिमिटेड के अनुसार, उसने संयुक्त उद्यम में अपने भागीदार टेलको से जमीन का पट्टा लिया था, हालांकि यह औपचारिक पट्टा था जो कि निष्पादित नहीं किया गया। TELCO के पास TISCO से 99 साल की अवधि के लिए एक पंजीकृत पट्टा था, जो उस समय सरकार

से वैध पट्टा था जब TISCO द्वारा TELCO को पट्टा प्रदान किया गया था। चूँकि भूमि TELCO के पास थी, जिसकी टाटा कमिंस लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी थी, इकाई लाभ के लिए पात्र थी। इसका अधिक महत्वपूर्ण दावा यह था कि वह उस इमारत का मालिक था जिसमें उसका कारखाना स्थापित किया गया था और अधिसूचना के पहले भाग के तहत, इमारत का विशेष स्वामित्व टाटा कमिंस लिमिटेड के पास था, वह छूट के लाभ का हकदार था। बिक्री कर जैसा कि पॉलिसी के खंड 16.1 और 16.2 में परिकल्पित है।

टाटा कमिंस लिमिटेड ने उपरोक्त दो अधिसूचनाओं के तहत छूट के लाभ का दावा करते हुए वाणिज्यिक कर उपायुक्त को आवेदन दिया।

2/12/1998 को, डिप्टी कमिशनर ने टाटा कमिंस लिमिटेड के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि टिस्को के पक्ष में सरकार से हेड लीज समाप्त हो गई थी और जब तक टिस्को के पक्ष में हेड लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ, टाटा कमिंस लिमिटेड, बिक्री कर के भुगतान से छूट के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं था। नतीजतन, टाटा कमिंस लिमिटेड द्वारा किया गया दावा खारिज कर दिया गया। तब से, हेड लीज का नवीनीकरण किया गया है।

इसके बाद, टाटा कमिंस लिमिटेड ने 2000 की रिट याचिका संख्या 2689 में डिप्टी कमिशनर के फैसले को चुनौती दी। डिवीजन बेंच ने माना कि टाटा कमिंस लिमिटेड के पास राज्य सरकार या टेल्को से वैध पट्टा नहीं है, वह छूट के लाभ का दावा नहीं कर सकती है। उपरोक्त दो अधिसूचनाओं के तहत। इस प्रकार, उपायुक्त के आदेश को बरकरार रखा गया।

इसके बाद टाटा कमिंस लिमिटेड ने 2000 की अपील संख्या 20375 और 20376 की विशेष अनुमति के लिए याचिका के माध्यम से डिवीजन बेंच के फैसले को इस न्यायालय में चुनौती दी।

अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, यह पाया गया कि उपायुक्त ने उपरोक्त दो अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक संयुक्त आयुक्त की मंजूरी के बिना उपरोक्त आदेश पारित कर दिया था। इसलिए, संयुक्त आयुक्त ने उपायुक्त और टाटा कमिंस लिमिटेड को नोटिस जारी कर छूट के सवाल की नए सिरे से जांच करने के लिए मामले के रिकॉर्ड मांगे।

इस प्रकार, जब सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय के लिए अपील करने की विशेष अनुमति की याचिकाओं पर विचार किया, तो संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को उसके संज्ञान में लाया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में, सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त आयुक्त को टाटा कमिंस लिमिटेड को एक अभ्यावेदन देने और आवश्यक दस्तावेज दाखिल करने का अवसर देने और उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय से प्रभावित हुए बिना मामले का निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस अदालत के समक्ष अपील में चुनौती दी गई।

दिनांक 24/5/2003 के आदेश के अनुसार, संयुक्त आयुक्त ने टाटा कमिंस लिमिटेड के उपरोक्त तर्कों पर ध्यान देने के बाद माना कि जिस भूमि पर टाटा कमिंस लिमिटेड द्वारा कारखाने का निर्माण किया गया था, वह टिस्को से टेल्को की उप-पट्टे की भूमि थी; कि, TELCO ने अपनी पट्टे पर दी गई भूमि का एक हिस्सा टाटा कमिंस लिमिटेड को आवंटित किया था, कि, TISCO और TELCO के बीच समझौते के अनुसार, बाद वाले को किसी अन्य कंपनी को भूमि का हिस्सा आवंटित करने का कोई अधिकार नहीं था; और वह, टाटा कमिंस लिमिटेड ने टिस्को से एक पट्टा निष्पादित करने का अनुरोध किया था लेकिन पट्टा समझौता निष्पादित नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में, संयुक्त आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्धारिती के पास उस भूमि पर न तो कानूनी अधिकार था, न ही स्वामित्व था, जिस पर कारखाना स्थापित किया गया था और न ही वह 15 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख प्रस्तुत करने की स्थिति में था। उपरोक्त दो अधिसूचनाओं के तहत छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए।

संयुक्त आयुक्त के दिनांक 24/05/2003 के इस आदेश को टाटा कमिंस लिमिटेड और टेल्को ने 2003 की रिट याचिका संख्या 2587 के माध्यम से चुनौती दी थी। आक्षेपित फैसले से, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना कि टाटा कमिंस लिमिटेड विशेष मालिक थी। वह भवन जिसमें फैक्ट्री स्थित थी और परिणामस्वरूप निर्धारिती ने उक्त अधिसूचना संख्या 478 के खंड 6 को पूरा/अनुपालन किया था, जिसे उक्त अधिसूचना संख्या 479 के खंड 8 के साथ पढ़ा गया था। डिवीजन बेंच ने निर्धारिती के रुपये का निवेश करने के तर्क पर भी गौर किया। परियोजना में 302 करोड़ रुपये और लगभग 600 करोड़ रुपये का कर चुकाया है।

आक्षेपित निर्णय के अनुसार, टाटा कमिंस लिमिटेड को उपरोक्त दो अधिसूचना संख्या 478 और 479, दोनों दिनांक 22/12/1995 के साथ पठित औद्योगिक नीति, 1995 के लाभ का हकदार

घोषित किया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार और वाणिज्यिक कर विभाग को 1/4/2004 से शुरू होने वाले लेखा वर्ष के लिए टाटा कमिंस लिमिटेड की बिक्री कर देयता के लिए 54.5 करोड़ रुपये की वापसी योग्य राशि को समायोजित करने का निर्देश दिया गया है।

उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया तथ्य यह है कि टाटा कमिंस लिमिटेड ने सब लीज के तहत टिस्को से ली गई जमीन में से 37.19 एकड़ जमीन टेल्को से प्राप्त कर अपने भवन में फैक्ट्री स्थापित की। इमारत का निर्माण टाटा कमिंस लिमिटेड द्वारा किया गया था। उद्योग ने अपना उत्पादन 1/1/1996 से शुरू किया था। टाटा कमिंस लिमिटेड के नाम से जाने जाने वाले संयुक्त उद्यम में TELCO 50% का मालिक था। भवन के स्वामित्व या 15 वर्षों के लिए पट्टे पर जोर देने का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना था कि उद्योग नीति के तहत दिए गए लाभ का लाभ लेने के बाद भाग न जाए और कंपनी वास्तव में एक वास्तविक निवेशक थी राज्य में उचित अवधि के लिए चलाए जाने वाले उद्योग में पूंजी। इसी पृष्ठभूमि में किसी को टाटा कमिंस लिमिटेड द्वारा किए गए निवेश को देखना होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, टाटा कमिंस लिमिटेड द्वारा 302 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, जिसमें 800 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और जिसने लगभग 600 करोड़ रुपये का कर चुकाया है। इन तथ्यों के संदर्भ में, हमारा विचार है कि यहां निर्धारिती फ्लाइ-बाय-नाइट ऑपरेटर नहीं हैं। हम इस फैसले को वर्तमान मामले के तथ्यों तक ही सीमित रख रहे हैं। उपरोक्त आंकड़े विवादित नहीं हैं। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि टाटा कमिंस लिमिटेड द्वारा स्थापित उद्योग राज्य की औद्योगिक वृद्धि एवं विकास में योगदान देगा।

हालाँकि, औद्योगिक नीति, 1995 की योजना को उपरोक्त दो अधिसूचनाओं के साथ समझने के लिए, हम यहां नीति के खंड 16 के साथ-साथ उपरोक्त दो अधिसूचनाओं के खंड 6 और खंड 8 को उद्धृत कर रहे हैं:

"16.1. कच्चे माल की खरीद पर बिक्री कर:

नई इकाइयों को राज्य के भीतर कच्चे माल की खरीद पर अपनी पसंद के अनुसार "सेट ऑफ" या "छूट" की सुविधा दी जाएगी। तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर को स्थगित करने का विकल्प चुनने वाली नई इकाइयों को (पैरा 16.2 के अनुसार) हालाँकि, पात्र हों या केवल कच्चे माल की खरीद पर "सेट ऑफ" करें। नई इकाइयों

के लिए छूट की अवधि इकाई के उत्पादन शुरू होने की तारीख से श्रेणी 'ए' के लिए 10 वर्ष और श्रेणी 'बी' जिलों के लिए 8 वर्ष तक सीमित होगी।

16.2. नई इकाइयों के लिए तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर:

नई इकाइयों को, खरीद पर बिक्री कर की "छूट"/सेट-ऑफ के लाभ के अलावा, बिक्री कर (बिहार बिक्री कर (बीएसटी) जी और केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) दोनों) के स्थगन या छूट को चुनने का विकल्प भी होगा। इकाई द्वारा किए गए निश्चित निवेश की 100% की सीमा के साथ, इकाई के उत्पादन की तारीख से श्रेणी 'ए' के लिए 10 साल और श्रेणी 'बी' जिलों के लिए 8 साल की अवधि के लिए तैयार माल की बिक्री पर, हालांकि, वे उद्योग जिन्हें पहले पैरा 15 में सूचीबद्ध 'श्रस्ट इंडस्ट्रीज' माना जाता है (दूरसंचार, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को छोड़कर) और साथ ही 'ए' श्रेणी के पिछड़े जिलों में स्थित उद्योगों के लिए सीमा या स्थगन निर्धारित का 150% होगा। निवेश। दूरसंचार, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के संबंध में निश्चित निवेश से जुड़ी मोहलत की सीमा इकाई द्वारा किए गए निश्चित निवेश का 300% होगी।

बिक्री कर स्थगन विकल्प के तहत एकत्र बिक्री कर की राशि को समान छह-मासिक किश्तों में इस तरह से वापस करना होगा ताकि पूरी राशि स्थगन विकल्प के शुरू होने से 13वें वर्ष तक वापस कर दी जाए।"

"अधिसूचनाएँ:

एसओ 478 दिनांक 22/12/1995।

6. इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि इकाई ऐसे भवन में स्थापित की जाए जो इकाई के मालिक/उद्यमी के विशेष स्वामित्व में हो या उसके किसी भागीदार या होल्डिंग कंपनी के स्वामित्व में हो। यदि किसी इकाई का कारखाना या कार्यशाला पट्टे पर ली गई भूमि या भवन पर स्थापित है, तो छूट केवल तभी दी जाएगी जब ऐसी भूमि या भवन या दोनों को न्यूनतम 15 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे

के माध्यम से अर्जित किया गया हो। वह पट्टा इकाई के मालिक या फर्म के किसी भागीदार या होल्डिंग कंपनी के पक्ष में होना चाहिए।

एसओ 479 दिनांक 22.12.1995:

8. इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक होगा कि इकाई ऐसे भवन में स्थापित की जाए जो इकाई के मालिक/उद्यमी के विशेष स्वामित्व में हो या उसके किसी भागीदार या प्रमोटर या होल्डिंग कंपनी के स्वामित्व में हो। यदि किसी इकाई का कारखाना या कार्यशाला पट्टे पर ली गई भूमि या भवन पर स्थापित है, तो छूट केवल तभी दी जाएगी जब ऐसी भूमि या भवन या दोनों को 15 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टे के माध्यम से अर्जित किया गया हो। वह पट्टा इकाई के मालिक या फर्म के किसी भागीदार या इकाई/फर्म की होल्डिंग कंपनी के पक्ष में होना चाहिए।"

अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह तर्क दिया गया कि अधिसूचना का पहला अंग केवल उन मूल्यांकनकर्ताओं पर लागू होता है जो भूमि और इमारतों के पूर्ण मालिक थे, एक निर्धारिती के विपरीत, जो भूमि का पट्टेदार था। और इमारत अधिसूचना के दूसरे भाग में शामिल है और चूंकि टाटा कमिंस लिमिटेड के पास उस भूमि पर कोई स्वामित्व नहीं है जहां इमारतों का निर्माण किया गया था, इसलिए वह उक्त अधिसूचना के संदर्भ में रियायत के लिए पात्र होने का दावा नहीं कर सकता था। टेलको द्वारा टाटा कमिंस लिमिटेड को तथाकथित अतिरिक्त पट्टा कानूनन अमान्य था। इस अंतिम प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टीजेएससीओ के पक्ष में हेड लीज का नवीनीकरण किया गया है और टिस्को से टेलको तक लीज विवाद में नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि TELCO संयुक्त उद्यम में 50% भागीदार है।

अधिसूचनाओं के साथ पढ़ी गई उपरोक्त नीति का विश्लेषण करने से पहले, "कर" शब्द के अर्थ को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। कर सामान्य राजस्व बढ़ाने के लिए एक भुगतान है। यह एक बोझ है। यह क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है या भुगतान करने की क्षमता। यह राज्य की कर लगाने की शक्ति का प्रकटीकरण है। किसी अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट कर दायित्व से छूट है। इसलिए, ऐसी प्रत्येक छूट अधिसूचना को सख्ती से पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि, जब एक निर्धारिती औद्योगिक नीति की शर्त के रूप में पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के

लिए कर छूट का वादा किया गया है, हमें औद्योगिक नीति के संदर्भ में कार्यान्वयन अधिसूचनाओं को पढ़ना होगा। ऐसे मामले में, छूट अधिसूचनाओं को पढ़ना होगा उदारतापूर्वक औद्योगिक नीति द्वारा परिकल्पित वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए और सख्त अर्थों में नहीं जैसा कि कर कानून के तहत कर दायित्व से छूट के मामले में होता है।

उपरोक्त परीक्षाओं को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, औद्योगिक नीति, 1995 को लागू करने के पीछे का उद्देश्य राज्य में स्थापित उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना था। प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में, औद्योगिक नीति में नवीकरण के विकल्प के साथ 99 वर्षों के लिए पट्टे पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए कंपनियों को विकास केंद्रों में भूमि/भवन के आवंटन की परिकल्पना की गई थी। प्रोत्साहनों के एक भाग के रूप में, खंड 16 के तहत यह भी परिकल्पना की गई थी कि राज्य में औद्योगिक विकास को बनाए रखने के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए बिक्री कर लाभ/छूट दी जाएगी। इस पृष्ठभूमि में, हमें औद्योगिक नीति, 1995 के खंड 16.1 और खंड 16.2 पर विचार करना होगा। ये दोनों अधिसूचनाएं औद्योगिक नीति, 1995 के तहत परिकल्पित नीति को प्रभावी बनाने वाले उपकरण मात्र हैं।

नीति की धारा 16.1 के तहत सभी नई इकाइयों को राज्य के भीतर कच्चे माल की खरीद पर "सेट ऑफ" "छूट" की सुविधा दी गई थी। श्रेणी "ए" में स्थित उद्योगों के लिए छूट की अवधि 10 वर्ष थी जिलों और श्रेणी "बी" जिलों में स्थित उद्योगों के लिए 8 वर्ष। अंतर्गत खंड 16.2 में नई इकाइयों को स्थगन या छूट चुनने का विकल्प दिया गया श्रेणी के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर का "ए" जिले और उत्पादन की तारीख से श्रेणी, "बी" जिलों के लिए 8 वर्ष इकाई द्वारा किए गए निश्चित निवेश की 100% की सीमा के साथ। हालाँकि, वे उद्योग जिन्हें "थ्रस्ट इंडस्ट्रीज" माना जाता था "ए" श्रेणी के पिछड़े जिलों में छूट की सीमा या स्थगन परिकल्पित निश्चित निवेश का 150% था।

इस प्रकार, "निवेश" औद्योगिक नीति के खंड 16 का आधार बना। कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारिती द्वारा निश्चित निवेश था, जो स्पष्ट है यदि कोई औद्योगिक नीति 1995 के खंड 16 के संदर्भ में 22/12/1995 दिनांकित दो अधिसूचनाओं को पढ़ता है और टाटा कमिंस किस मानदंड को पूरा करता है। लिमिटेड इस मामले में, अर्थात्, यह

उस इमारत का मालिक है जिसमें इसका कारखाना स्थित है। अधिसूचना(ओं) के पीछे अंतर्निहित तर्क यह है कि निर्धारिती को उस भवन के स्वामित्व में धन का उपयोग करना चाहिए जिसमें कारखाना स्थित है या न्यूनतम 15 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर ली गई इमारत में धन का अवक्षेपण करना चाहिए। कि बिना निश्चित निवेश वाली फर्जी कंपनियां केवल कर छूट पाने के इरादे से स्थापित नहीं की जाती हैं।

अधिसूचना संख्या 478 और 479 का दायरा:

शुरुआत में हम दोहराते हैं कि यदि कोई प्रोत्साहन नीति के आलोक में अधिसूचना (अधिसूचनाओं) को पढ़ता है तो यह स्पष्ट है कि प्रोत्साहन उस इकाई के लिए स्वीकार्य है जो उस भवन का मालिक है जिसमें वह स्थित है जहां से औद्योगिक उत्पादन शुरू होता है या यह (इकाई) एक पट्टाधारित परिसर (भवन या भूमि या दोनों) में स्थित है, बशर्ते कि पट्टा न्यूनतम 15 वर्ष की अवधि का हो। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पात्रता मानदंड एक वास्तविक निवेशक द्वारा एक निश्चित निवेश है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हमें नीति के आलोक में अधिसूचना(अधिसूचनाओं) की व्याख्या के अनुसार चलना होगा। हालाँकि, यदि कोई अधिसूचना(अधिसूचनाओं) की कड़ाई से व्याख्या करता है तो भी हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि अधिसूचना(अधिसूचनाओं) का पहला भाग, दूसरे भाग से अलग, 'भूमि' का उल्लेख नहीं करता है। यदि विभाग के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए कि अधिसूचना का पहला भाग केवल तभी लागू होगा जब टाटा कमिंस लिमिटेड उस भूमि और भवन का मालिक है जिसमें उसका कारखाना स्थित है, तो हम न केवल अधिसूचना की एक संकीर्ण व्याख्या कर रहे हैं जो कि प्रोत्साहन नीति के अंतर्निहित उद्देश्य को विफल करना, लेकिन यह उक्त अधिसूचना (अधिसूचनाओं) के मूल पाठ के विरुद्ध भी होगा जो अधिसूचना के पहले भाग से "भूमि" शब्द को हटा देता है।

निष्कर्ष निकालने से पहले, हम दोहरा सकते हैं कि मामले के एक चरण में विभाग ने यह स्थिति ली थी कि टाटा कमिंस लिमिटेड लाभ का हकदार नहीं था क्योंकि टिस्को के पक्ष में हेड लीज राज्य सरकार द्वारा नवीनीकरण के लिए लंबित थी और जब तक कि राज्य ने टिस्को के पक्ष में पट्टे का नवीनीकरण किया, टाटा कमिंस लिमिटेड रियायत के लाभ का हकदार नहीं था। हमें सूचित नहीं किया गया है कि राज्य सरकार ने टिस्को के पक्ष में हेड लीज का नवीनीकरण

किया है, जिसने बदले में उसका एक हिस्सा टेल्को को उप-पट्टे पर दे दिया है, जिसकी संयुक्त उद्यम, अर्थात् टाटा कमिंस लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी है।

इन परिस्थितियों में, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या उपरोक्त दो अधिसूचनाएँ प्रोत्साहन नीति के प्रतिकूल हैं। हालाँकि, हमने मामले में इस अदालत के फैसले के अनुपात पर ध्यान दिया है *बिहार राज्य और अन्य आदि बनाम सुप्रभात स्टील लिमिटेड और अन्य आदि*, [1999] आई एससीसी 31 में रिपोर्ट की गई, जिसमें यह माना गया है कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति को लागू करने के लिए अधिसूचनाएं प्रोत्साहन नीति को ओवरराइड नहीं कर सकती हैं।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर, हमें इस सवाल की जांच करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या यहां ऊपर उद्धृत दो अधिसूचना संख्या 478 और 479 प्रोत्साहन नीति के प्रतिकूल हैं।

निष्कर्ष निकालने से पहले, हम बता सकते हैं कि दिनांक 26/3/2004 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने, अंतरिम उपाय के माध्यम से, अपीलकर्ता को 1/4/ से शुरू होने वाले लेखांकन वर्ष के लिए 40 करोड़ रुपये की वापसी योग्य राशि को समायोजित करने का निर्देश दिया। 2004 में, शेष राशि टाटा कमिंस लिमिटेड को वापस करने का आदेश दिया गया था, जिसने अपीलकर्ता को इस नागरिक अपील में राज्य के सफल होने की स्थिति में 9% की दर से ब्याज के साथ शेष भुगतान वापस करने का वचन दिया था। हालाँकि, चूंकि हम राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज कर रहे हैं, इसलिए टाटा कमिंस लिमिटेड द्वारा राज्य को शेष राशि यानी (14.5) करोड़ रुपये ब्याज के साथ वापस करने का सवाल ही नहीं उठता।

तदनुसार, हमें इस सिविल अपील में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया गया।

उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, हमें अधिसूचना संख्या के खंड 6 और 8 की वैधता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। क्रमशः 478 और 479 और तदनुसार, सिविल अपील नं. 2004 के 1006 का भी निपटान कर दिया गया है, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

वी.एस.

अपीलें खारिज.

झारखंड राज्य और अन्य बनाम टाटा कमिंस लि. और अन्य।

चंद्रकांत शुक्ल की देखरेख में शशिप्रभा द्वारा अनुवादित।